इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 570]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2017—आश्विन 26, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ ए-8-72-2017-1-पांच (135)

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, माल जिनका विवरण निम्न तालिका के स्तंभ(3) में विनिर्दिष्ट तथा जो उक्त तालिका के स्तंभ(2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, राज्य के भीतर आपूर्ति पर, 2.5 प्रतिशत की राज्य कर

की दर स्चित करती है, पर नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं0	अध्याय उपशीर्ष/शीर्ष/ टैरिफमद	माल का विवरण	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19 या 21	केन्द्रीय सरकार या	यदि खाँद्य निर्मितियों का प्रदायक ऐसे किसी
		राज्य सरकार द्वारा	अधिकारी से, जो भारत सरकार के उप सचिव की
	*	सम्यक रूप से	पंक्ति से नीचे का नहीं है या सबंधित राज्य सरकार में
		अनुमोदित किसी	उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं, इस आशय का
		कार्यक्रम के अधीन	प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि ऐसी खाद्य निर्मितियां

समाज के आर्थिक रूप केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से से कमजार वर्गों को अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक

वितरित कर दी गई है।

स्पष्टीकरण-

(1) "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का

के

और

में

खादय

निशुल्क वितरण

युनिट

निर्मितियां ।

रखी

आशयित

गई

अभिधानों

- 51) की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
- (2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण परमार, उपसचिव.

रूप से कमजोर वर्गों को ऐसे माल की आपूर्ति की

तारीख से पांच मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय कर आयुक्त

या राज्य कर आयुक्त के इस निमित्त अनुज्ञात करे,

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-ए-3-72-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-72-2017-1-पांच (135), दिनांक 18 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण परमार, उपसचिव.

No. F-A-3-72-2017-1-V (135)

Bhopal, the 18th October 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the state tax rate of 2.5 per cent on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), subject to the condition specified in column (4) of the Table below, namely:-

Table

	· ·		1 auto
Sl. No.	Tariff item, sub- heading, heading or Chapter	Description of Goods	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19 or 21	Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or State Government.	approved by the Central Government or the

Explanation. -

(1) In this notification, "tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ARUN PARMAR, Dy. Secy.